

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर

email id- balikagrahajmer@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- 3274

दिनांक : 30.03.2022

खुली प्रतियोगी बोली सूचना संख्या 03 / 2021-22

इस कार्यालय के अधीन संचालित आवासीय गृह में रसोईया, सुरक्षा गार्ड, स्वीपर, केयर टेकर एवं सहायक कर्मचारी की सेवाएं वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जॉब बेसिस पर लेने हेतु श्रम विभाग में पंजीकृत संवेदको/संस्थाओं से शर्तरहित निविदा दिनांक 08.04.2022 तक आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट <http://sje.rajasthan.gov.in> या लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in एवं डी आई पी आर की वेबसाईट www.dipronline.org पर देखी जा सकती है।

UBN:- CED2122SSOB00075

NIB CODE: CED2122A0072

mmg
30.3.2022
अधीक्षक

राजकीय बालिका गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

दिनांक : 30.03.2022

क्रमांक :- 3275-81

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभागीय मेल आई.डी. पर भिजवाकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का नियमानुसार आपके विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावे एवं निविदा सूचना एक क्षेत्रीय स्तर के मुख्य दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तें भेजकर निवेदन हैं कि नियमानुसार विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करावें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/जिला परिषद/नगर निगम अजमेर।

mmg
30.3.2022
अधीक्षक

राजकीय बालिका गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर

email id- balikagrahajmer@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- 3255

दिनांक:- 29.03.2022

बिड आमंत्रण सूचना संख्या ...03.../2022-23

बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकीय बालिका गृह लोहागल, अजमेर आवासीय गृह के सुचारु संचालन हेतु सुरक्षागार्ड, रसोईया, स्वीपर, केयर टेकर, सहायक कर्मचारी की सेवायें वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जॉब बेसिस पर लेने हेतु राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंसी (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2005, राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंसी (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों/संस्थाओं/सेवाप्रदाता एजेंसियों से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत शर्त रहित खुली प्रतियोगी द्वि प्रकर्मि बोली (मोहर बन्द लिफाफो में) आमंत्रित की जाती है :-

महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय

क्र. स.	विवरण	विवरण
1	जॉब बेसिस सेवा आपूर्ति का कार्य विवरण	शिड्यूल G के अनुसार
2	अनुमानित लागत	9.00 लाख रुपये
3	बिड प्रपत्र शुल्क	500.00 रुपये
4	बिड सिक्यूरिटी	18000/-
5	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	30.03.2022 सायं 6.00 बजे से
6	तकनीकी बिड व वित्तीय बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	08.04.2022 दोपहर 1.00 बजे तक
7	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	08.04.2022 दोपहर 3.00 बजे
8	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	11.04.2022 दोपहर 3.00 बजे

बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट <http://sje.rajasthan.gov.in> या लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है/डाउनलोड की जा सकती है। तकनीकी व वित्तीय बिड के पृथक-पृथक मोहरबन्द लिफाफो में निर्धारित तिथि व समय तक प्रस्तुत की जा सकती है।


अधीक्षक

राजकीय बालिका गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर
email id- balikagrahajmer@rajasthan.gov.in

दिनांक:-

तकनीकी बिड

1. उपापन संस्था का विवरण : अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर
2. कार्य का विवरण : रसोईया, सुरक्षा गार्ड, स्वीपर, केयर टेकर व सहायक कर्मचारी की जॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्य
3. अनुमानित लागत : रु: 9.00 लाख
4. बिड आमंत्रण संख्या : दिनांक
5. बोलीदाता का विवरण :
(1) फर्म/संस्था का पूरा नाम :
.....
(2) पूर्ण पता :
.....
(3) संस्था का प्रकार
(एनजीओ/फर्म/कं./अन्य):
(4) टेलीफोन नं. :
(5) मोबाईल नं. :
(6) ई-मेल पता :
6. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :-

क्र.सं.	प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रकार एवं विवरण	हां या नहीं	जारी होने की तिथि/वैधता अवधि / बैंक का विवरण	पृष्ठ सं०
1.	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500 /- जमा कराने का ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक नम्बर दिनांक प्रस्तुत किये जाने का विवरण			
2	बिड सेक्युरिटी राशि 18000/- का विवरण			
3	10 मैन पावर सप्लाय हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र			
4	फर्म/संस्था के पंजीकरण की सूचना आदि			
	A. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970			
	B. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952,			
	C. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948,			
	D. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी नं.),			

	E. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत			
	F. इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956			
	G. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958			
	H. आयकर (पैन नम्बर)			
	I. प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी एक्ट, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट, 2006 के तहत जारी लाईसेंस			
5	गत तीन वित्तीय वर्षों का सीए का ऑडिट रिपोर्ट (2018-19से 2020-21)			
6	गत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न (2018-19से 2020-21)			
7	गत वर्षों में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र (100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पर शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित)			
8	Annexure '1' संलग्न करना। (गत तीन वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम रु: 9.00 लाख रुपये का टर्न ओवर) सी.ए. द्वारा जारी प्रमाणपत्र			
9	परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 एवं A,B,C,D			
10	बैंक का विवरण			
	A. बैंक खाताधारक संस्था का पूरा नाम			
	B. बैंक खाता संख्या,			
	C. बैंक का नाम व शाखा का नाम			
	D. बैंक खाते का प्रकार			
	E. आई एफ एस सी कोड			

7. इसके अलावा हमारे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:-

1.
2.
3.
4.
5.

नोट- संलग्न अनुज्ञा पत्रों, रिटर्न एवं अन्य दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या सम्बन्धित के समक्ष निर्धारित कॉलम में अंकित करना सुनिश्चित करें।

8. मैं/हम कार्यालय अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक दिनांक मैं वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) मैं/हम दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज वैधानिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरुद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
दिनांक

राजकीय बालिका गृह अजमेर

दिनांक :

वित्तीय निविदा

संवेदक के माध्यम से जॉब बेसिस सेवाओं के उपापन के लिए अपनी निविदा
दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:-

(संवेदक द्वारा भरा जाना)

क्रम स.	जॉब बेसिस कार्य की प्रकृति	श्रमिक की श्रेणी	श्रमिक की संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर प्रति व्यक्ति प्रति माह	EPF की दर 13% से राशि	ESI की दर 3.25% से राशि	कुल राशि	संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति सेवा दर का प्रतिशत व राशि	संवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा दर कॉलम 7 व 8 का योग
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	सुरक्षागार्ड	कुशल	3	7176/-	933/-	233/-	8342/-		
2	रसोईया	कुशल	1	7176/-	933/-	233/-	8342/-		
3	स्वीपर	कुशल	1	7176/-	933/-	233/-	8342/-		
4	केयर टेकर	कुशल	3	7176/-	933/-	233/-	8342/-		
5	सहायक कर्मचारी	अकुशल	1	6552/-	852/-	213/-	7617/-		

1. GST नियमानुसार लागू होगा जो की पृथक से देय होगा।
2. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिव्यक्ति सेवा दर का प्रतिशत में शून्य दर स्वीकार्य नहीं होगी।
3. श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन राज्य सरकार की अधिसूचना / श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर परिवर्तन अनुसार परिवर्तित रहेगी।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदाता मय सील

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह, बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर में
जॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश एवं शर्तें

Important Instruction : The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012'k [herein after called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013'k [herein after called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in> . Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. निविदा प्रस्तुत करने की विधि व प्रक्रिया :

- (1) बोली प्रस्तुत करने के इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रपत्र <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। एवं विभागीय वेबसाईट <http://sjerajasthan.gov.in> या कार्यालय से भी निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्राप्त की जा सकती है।
- (2) बोली निर्धारित फोरमेट में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा से संबंधित वित्तीय बिड प्रपत्र के सहित सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हुए तथा आवश्यक अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करने के उपरान्त निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि व समय पश्चात डाक द्वारा प्राप्त बोली प्रपत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः बोलीदाता अपनी बोली प्रपत्र निर्धारित तिथि से पूर्व स्वयं के स्तर से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे (डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त बोली प्रपत्रों हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे)
- (3) वित्तीय बिड प्रपत्र निर्धारित फोरमेट में पृथक लिफाफे में मोहरबन्द कर प्रस्तुत की जावेगी। निविदादाता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही दरें वित्तीय बिड प्रपत्र के अलावा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं की जावें।
- (4) तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड को खोला जावेगा।
- (5) वित्तीय बिड व तकनीकी बिड पृथक-पृथक मोहरबन्द लिफाफों में उन पर फर्म का नाम पता सम्पर्क नम्बर व तकनीकी बिड/वित्तीय बिड स्पष्ट रूप से अंकित कर निर्धारित तिथि व निर्धारित समय तक प्रस्तुत कर सकेंगे। जिन्हे निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

2. बिड प्रस्तुत करने के लिए पात्रता:

कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था जो राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958, या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, प्राईवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2006 के अन्तर्गत जो इनमें पंजीकृत हो तथा गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम टर्नओवर रुपये 9.00 लाख (बोली मूल्य के बराबर) होना आवश्यक है। इस हेतु Annexure-1 भर कर व पंजीकरण की सूचना Annexure-2 तथा बैंक लिस्ट भरकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा इससे सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रति लगाना आवश्यक होगा।

नोट :- सिक्यूरिटी सप्लाई लाइसेन्स व अन्य सेवा प्रदाता लाइसेंस होना आवश्यक है। बिना इन दोनों अथवा दोनों में से एक के अभाव वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

h

राजकीय बालिका गृह, अजमेर

3. बिड की सामान्य निर्देश एवं शर्तें :

- (1) उपापन संस्था— कार्यालय अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह, बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर
- (2) उपापन की पद्धति— खुली प्रतियोगी बोली पद्धति से दर संविदा हेतु द्वि प्रकमी बोली।
- (3) बोली प्रपत्रों का मूल्य—रूपये 500/- जिसका बैंकर्स चेक/डी.डी., अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर के पक्ष में देय होगा।
- (4) बोली प्रतिभूति 2 प्रतिशत की दर से 18000/- बैंकर चैक/ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करनी होगी जो कि अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर के पक्ष में हो।
4. वित्तीय बिड प्रस्तुत करने वाले को दर BOQ निर्धारित कॉलम में भरकर एक पृथक मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
6. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्राईवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2006 के अर्न्तगत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की स्व सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ इस उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
7. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करवाई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
8. श्रम, विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
9. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना के तहत समय-समय पर वृद्धि होने की दशा में उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
10. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अशंदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
11. संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर डिस्ट्रे बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रकृति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाइन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने, की शिकायत करने सम्बन्धित प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
12. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा। प्रस्तुत चालानों के साथ लगाये गये कर्मचारियों के EPF, ESI, के चालानों में नामों व EPF/ESI खाता संख्या, आधार कार्ड नम्बर सहित डिटेल प्रस्तुत करनी होगी।
13. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि का

2

राज्य बालिका गृह, अजमेर

पालन नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये सर्वेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

14. सर्वेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी सर्वेदक की ही होगी। सर्वेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये। वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माही के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दायित्वा के निर्वहन का उत्तर दायित्व सर्वेदक का होगा।
15. यदि सर्वेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी सर्वेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिये उचित कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।
16. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमूक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व सर्वेदक का होगा। कार्यालय/विभाग इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी शारीरिक क्षति की दशा में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व सर्वेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. यदि सर्वेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में सर्वेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
19. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना विभागीय अधिकारी को लिखित में टेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म को मुक्त नहीं किया जाएगा।
20. निविदा के साथ सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
21. निविदा खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
22. बिड प्रतिभूति बॉन्ड के तहत निम्न मामलों में कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
 - (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है या उसमें कोई उपान्तरण करता है।
 - (2) निविदादाता निर्धारित दिनांक तक अनुबंध करने में असफल रहता है।
 - (3) निविदादाता आदेश देने के बाद निर्धारित अवधि से प्रतिभूति राशि जमा कराने में असफल रहता है।
23. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Security):**— सफल निविदादाता की दर अनुमोदन होने पर 7 दिवस में कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत (रुपये 45,000/-) के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी
 - (1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक गारन्टी व फिक्स डिपोजिट के रूप में स्वीकार की जायेगी जो की **Superintendent Rajkiya Balika Grah Baal Adhikarita Vibhag Ajmer** के पक्ष में देय हो।
 - (2) प्रतिभूति — बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से पूरी अनुबन्ध अवधि की पूर्ण कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

अभिषेक
राजस्थान राज्य सरकार

24. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त करली जायेगी :-

- (1) संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर।
- (2) सेवायें/सन्तोष जनक ढंग से कार्य करने में असफल रहने पर।
- (3) कार्य अवधि के दौरान स्वेच्छा से कार्य छोड़कर जाने की स्थिति में

25. श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आयकर विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, नगरपालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम आदि से संबंधित समस्त प्रकार की फीस/पेनल्टी/शास्ति के भुगतान के लिए यह कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

26. भुगतान : बोलीदाता को निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा : -

- (अ) भुगतान अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर द्वारा आपके नियोजि कामगारों की उपस्थिति जाँच पश्चात् स्वीकृत दर अनुसार देय होगा।
- (ब) कार्मिक को साप्ताहिक अवकाश देना होगा एवं साप्ताहिक अवकाश के दिन अतिरिक्त कार्मिक लगाने होंगे/उपलब्ध कार्मिकों से अतिरिक्त कार्य कराना होगा, जिसका न्यूनतम मजदूरी की दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा।
- (स) न्यूनतम मजदूरी भुगतान का प्रमाण स्वरूप कामगारों को बैंक खाते में जमा की बैंक अन्तरण सूची आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (द) समय-समय पर लागू श्रम अधिनियम एवं नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।
- (य) सरकार को देय समस्त करों की कटौती बोली दाता के बिल से की जायेगी।
- (र) भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य करने के उपरान्त पिछले माह के ई.पी.एफ. ई.एस.आई. व अन्य के खातों में जमा राशि का चालान एवं बैंक खातों में जमा का विवरण प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें बिल से घटाया जावेगा।
- (ल) जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा तथा इसे संबंधित मद में जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
- (व) श्रम विभाग के नियम अनुसार मासिक परिश्रमिक 26 दिवस का माह मानकर की जायेगी।

27. अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जावेगी यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह संभव नहीं हो तो राजस्थान लोक मांग अधिनियम PDR (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

28. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids) : बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामलों में तथाकथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटियों रह गई है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

29. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार : उपापन संस्था

बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

30- परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity):

1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई सेवा उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिश्चिit परिमाण से कम/ज्यादा उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। सेवाप्रदाय का पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं मूल आदेशित मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।

31- अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award) :

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा। जिसकी बोली स्वीकार या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

32- सेवाओं की गारंटी/वारंटी – बोली दाता को उपापन की सेवाएँ बोली दस्तावेजों एवं समय-समय पर उपापन संस्था द्वारा दिये निर्देशों के अनुरूप संपादित करनी होगी। निरीक्षण के दौरान सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उपापन संस्था को अनुबन्ध समाप्त करने या ऐसा निर्णय लेने का अधिकार होगा जो वह युक्तियुक्त समझे। उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं बोली दाता के लिए बाध्यकारी होगा।

33- करार का निष्पादन (Execution of Agreement) :

1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम दस दिवस में स्वयं के खर्च पर एक करार पत्र (राशि रु 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर) निष्पादित करना आवश्यक है विशेष परिस्थितियों में कार्यालय को अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों की बोली लगाने वालों को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुद्ध प्रतिपड्त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

34- सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity): उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति-

- 1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- 2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह रहने का प्रयास करता हो।
- 3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य में वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- 4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- 5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- 6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- 7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- 8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

35- हित का विरोध (Conflict of Interest) :

- 1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- 2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं,
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है,
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है,
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है, जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो,
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि वह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है, या
 - (च) बोली लगाने वाले या उससे सम्बद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये गये हैं के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो सम्बद्ध है और न ही सम्बद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

36- बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग : अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबंध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

37- वाद-विवाद : किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में प्रकरण पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्षों को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में स्वयं अथवा विभाग के

सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगा, यह अधिकारी इस संविदा से संबंधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- 38-** न्यायिक क्षेत्र : इस निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र अजमेर शहर होगा।
- 39-** जॉब बेसिस सेवा चौकीदार, रसोईया, स्वीपर, केयर टेकर एवं सहायक कर्मचारी के कार्यों की वित्तीय निविदा को वित्तीय स्वीकृति के लिए दरों के संबंध में पृथक पृथक ईकाई नहीं माना जायेगा सम्पूर्ण समेकित हितकारी लाभप्रद दरों को ही स्वीकृत करने का अधिकार उपापन समिति का सुरक्षित है।
- 40-** सामान्य वित्तीय लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
- 41-** कार्य की अवधि कार्यादेश तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अवधि बढ़ाने या घटाने का अधिकार अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग अजमेर के पास होगा। स्थायी कार्मिक उपलब्ध होने की दशा में ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।
- 42-** यदि पूर्व में कोई रिट/वाद न्यायालय में विचाराधीन होने पर उनके निर्णय/स्टे वेकेट होने तक निविदा में दर्शित कामगारों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है अथवा उनके स्थान पर नहीं भी रखा जा सकता है।
- 43-** किसी संवेदक/संस्था द्वारा गलत/मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर कार्यादेश रद्द कर दिया जायेगा व प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी एवं संवेदक संस्था को ब्लेकलिस्टेड कर दिया जायेगा।
- 44-** निविदा में दरें समान आने पर उपापन समिति द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों पर निविदा का निर्णय किया जावेगा—

क. सं.	चयन का आधार	कार्यकुशलता का विवरण		चयन के लिए निर्धारित अंकों की संख्या
1.	गत तीन वित्तीय वर्षों (2018-19 से 2020-21) का औसत टर्नओवर सी.ए. की रिपोर्ट के आधार पर एनेक्सर- 1द्व	अ.	50 लाख तक	10 अंक
		ब.	50,00,001 से 1 करोड़	15 अंक
		स.	1 करोड़ से अधिक	20 अंक
		द.	यदि एक से अधिक निविदादाता का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हैं तो सबसे अधिक टर्नओवर वाले केवल एक संवेदक को 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे।	
2.	संवेदक/फर्म माह फरवरी-2022 में उपलब्ध कराये गये कुल मैन-पावर कार्मिकों की संख्या व उनको देय पीएफ एवं ईएसआई माह फरवरी 2022 में कितने कार्मिकों का जमा कराया गया है। चालानों की प्रति संलग्न करें मय कार्मिक विवरणद्व • फरवरी-2022 में कुल मैन पावर की संख्या अंकित करें—	अ.	1-25 कार्मिकों तक	10 अंक
		ब.	26-50 कार्मिकों तक	15 अंक
		स.	51-75 कार्मिकों तक	20 अंक
		द.	75 कार्मिकों से अधिक यदि एक से अधिक निविदादाता हैं तो सबसे अधिक कार्मिक सप्लाई करने वाले केवल एक संवेदक को 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे	
3.	संवेदक / फर्म का रजिस्ट्रेशन के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।	अ.	राजस्थान राज्य के बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	10 अंक
		ब.	राजस्थान राज्य के अंदर किन्तु अजमेर संभाग से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	15 अंक

राजकीय बालिका गृह, अजमेर

	स.	अजमेर संभाग के अंदर किन्तु अजमेर जिले से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	20 अंक
	द.	अजमेर जिले की फर्म/संवेदक होने पर	25 अंक

यदि इसके उपरान्त भी दो या दो से अधिक संवेदकों को एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो उपापन समिति द्वारा किसी एक संवेदक का चयन सर्वमान्य होगा। जिसके अंतिम निर्णय का समस्त अधिकार उपापन समिति को होगा।

45- अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार लागू होंगी।

46- Anexure.1 , 2, 3, 4 व A,B,C,D पर संलग्न करना आवश्यक है। नियोजित होने वाले कामगारों का प्रकार, संख्या, कार्य की प्रकृति एवं योग्यता शिड्यूल जी के अनुसार होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षक
राजकीय बालिका गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

शपथ पत्र

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 46 तक को भली-भांति पढ़ लिया है, समझ लिया है एवं इन समस्त शर्तों की पूर्ण पालना हेतु सहमत हूँ तथा पूर्ण पालना की निष्ठापूर्वक पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

h
अधीक्षक
राजकीय बालिका गृह, अजमेर

CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER

It is to certify that the average annual turnover of M/s.

Address.....

for the last three financial year supply in of regarding work was

Sr. No.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (Rs. In Lakh)	Remarks
1.	2018-19		
2.	2019-20		
3.	2020-21		

Date:

Place:

Signature of the Auditor/Seal

Chartered Accountant
(Name and Address)

Tel. No. :-

Mob.No. :-


ह
अमरसिंह
राजकीय शौचालय रोड, अनापूर

Annexure '2'

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:-

क. सं	विवरण	रजि० सं०	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956				
7	प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सीस (रेगुलेशन) एक्ट 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सीस (रेगुलेशन) एक्ट 2006 के अन्तर्गत जारी लाईसेन्स संलग्न करना				
8	बिड प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं प्रतिभूति राशि का डी.डी. संलग्न करना होगा ।				
9	किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करना ।				
10	10 मैन पावर सप्लाय हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का प्रमाण संलग्न करना				
11	गत तीन वित्तीय वर्षों का सीए का ऑडिट रिपोर्ट (2018-19 से 2020-21) संलग्न करना				
12	गत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न (2018-19 से 2020-21) संलग्न करना				
13	गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम 10 लाख रुपये का टर्न आवर संलग्न करना				
14	परिशिष्ट 1,2,3,4 एवं A,B,C,D संलग्न करना				

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक :-


 अधीक्षक
 राजकीय बालिका गृह, अजमेर


घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि यह संस्था/फर्म श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या.....दिनांक है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा उचित कानूनी कार्यवाही कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर सकेगा।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील


अधीक्षक
राजकीय कारिगार मूल आजादे

निविदादाता की घोषणा

बोली की समस्त/समझ लिया है जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा उपापन पारदर्शिता अधिनियम की धारा 46 एवं उपापन नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा/ कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा। तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय सील

25
असौस्तिक
राज्यपाल कार्यालय गुरु अचारे

Annexure – A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest:

Any person participating in the procurement process shall –

- a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g) disclose conflict of interest, if any; and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

2-

अधीनस्थ

महाराष्ट्र शासन, पुणे, राज्याचे

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submit to superintendent Govt.Girls home ajmer For procurement of.....in response to their notice Inviting Bids No.....Date.....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer. not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition;

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Desination:

Address:

2-
राजस्थान प्रसारण निगम लि.
जयपुर

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority A.D. ICPS Ajmer

The designation and address of the Second Appellate Authority is **DIRECTOR Directorate for Child Rights, Jaipur**

1. **Filing an appeal** :- If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:
Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.
Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
 - (a) determination of need of procurement;
 - (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
 - (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
 - (d) cancellation of a procurement process;
 - (e) applicability of the provisions of confidentiality.
5. Form of Appeal

20
अभिषेक
दिनांक 12 अक्टूबर

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

7-
अधीक्षक
राज्य प्रशासन विभाग, दिल्ली

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

1. Official address, if any:

2. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place

Date

Appellant's Signature :

2-
 अधीक्षक
 राजकीय बालिका मध्य शाला

Annexure – D: Additional Conditions of Contract

1- Correction of Arithmetical Errors :

Provided that the bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
- IV. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2- Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Documents may be increased or decreased, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. Additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% and 50% of Quantity of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

2/-
आयुक्त
राजकीय बाजिका मू. अजमेर

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय बालिका गृह बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

balikagrahajmer@rajasthan.gov.in

शिडयूल-जी

क्र० सं०.	जॉब बैसिस सेवा कार्य प्रकृति	वांछित सेंवाकार	कार्य का विवरण	जॉब बैसिस का औचित्य	अर्हता
1	केयर टेकर	3 महिला (कुशल)	<p>राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 के अनुसार गृहों में केयर टेकर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बालिकाओ के साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार करना। 2. बालिकाओ की उचित देखरेख करना तथा बालकों के कल्याण का कार्य करना 3. बालिकाओ के बीच अनुशासन बनाये रखना 4. सफाई और स्वच्छता बनाये रखना। 5. दैनिक कार्यों का दक्षता पूर्ण रीति से क्रियान्वयन तथा इसमें बालिकाओ की सह सभागिता सुनिश्चित करना। 6. गृह की सुरक्षा और संरक्षण व्यवस्था की देखभाल। 7. बालिकाओ का, वे जब कभी भी गृह से बाहर जाते हैं, मार्ग रक्षण करना। 	<p>बालिकाओ के बीच अनुशासन बनाये रखना एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखना। कार्य तीन पारियों में सम्पादित होगा। प्रातः 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक। दोपहर 2.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक। रात्री 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक। प्रत्येक पारी में एक केयर टेकर अपनी सेवाएं देंगे जिन्हे आवश्यकतानुसार समय समय पर पारी परिवर्तन अधीक्षक अपने स्तर पर निर्धारित करेगा।</p>	<p>न्यूनतम 12 वीं पास होना आवश्यक है।</p>
2.	सुरक्षा गार्ड	3 महिला (कुशल)	<ol style="list-style-type: none"> 1. गृह में आवासित बालिकाओ की सुरक्षा का कार्य करना। 2. सुरक्षा गार्ड द्वारा परिसर के मुख्य द्वार पर आने जाने वाले आगन्तुको व आवासित बालिकाओं के परिसर के बाहरी क्षेत्र में पूर्ण निगरानी का कार्य करना। 3. आगन्तुको के आवागमन को रजिस्टर में इन्द्राज करना व उनको प्रस्थान तक पूर्ण निगरानी करना। 4. आवासित बालको के बिमार होने पर उन्हें अस्पताल(जे.एल.एन./डिस्पेन्सरी जैसा भी 	<p>गृह परिसर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एवं अन्दर चैनल गेट पर चौकिदारी के सेवा कार्य की आवश्यकता है। कार्य तीन पारियों में सम्पादित होगा। प्रातः 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक। दोपहर 2.00 बजे से</p>	<p>गार्ड हेतु न्यूनतम आठवीं पास होना आवश्यक है।</p>

अधीक्षक
राजकीय बालिका गृह, अजमेर

			<p>स्थिति हो) ले जाना तथा चिकित्सक के परामर्श अनुसार उनकी देखरेख करना व आवश्यकता होने पर उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़े तो उनकी चिकित्सालय में देखभाल व सुरक्षा करना।</p> <p>5.आवासितों के साथ उत्तम व्यवहार की अपेक्षा की जाती है कठोर व अप्रिय भाषा का उपयोग नहीं करना।</p> <p>6.किसी भी अवांछनिय/अप्रिय घटना होने पर तत्काल अधीक्षक के संज्ञान में लाना होगा।</p> <p>7.अन्य कार्य जो अधीक्षक निर्देशित करें सम्पादित करना होगा।</p> <p>8. पुरुष गार्ड होने की स्थिति में केवल गृह परिसर के बाहर मुख्य दरवाजे पर ही सेवा कार्य करवाया जावेगा।</p>	<p>रात्री 10.00बजे तक।</p> <p>रात्री 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक।</p> <p>प्रत्येक पारी में एक गार्ड अपनी सेवाएं देंगे जिन्हें आवश्यकतानुसार समय समय पर पारी परिवर्तन अधीक्षक अपने स्तर पर निर्धारित करेगा।</p>	
3.	रसोईया	1 महिला (कुशल)	<p>1.आवासनियों हेतु भोजन/ नाश्ता/ चाय/दुध बनाना एवं उनको परोसने की सम्पूर्ण प्रक्रिया करना। जिसमें स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना होगा।</p> <p>2.रसोइयो को समय पर उपस्थित होना होगा तथा निर्धारित पारी व समयानुसार भोजन,नाश्ता तैयार करना व कार्य उपरान्त सम्पूर्ण सामग्री का निबटान व साफ-सफाई कर पूर्ण करना होगा।</p> <p>3.आवासियों के साथ किसी भी प्रकार की कठोर या अप्रिय भाषा का प्रयोग न करना।</p> <p>4.आवासियों को शुद्ध एवं ताजा भोजन देना।</p> <p>5.किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का अपव्यय न करना।</p> <p>6.खाद्य सामग्री के दुरुपयोग /खराब किये जाने पर नुकसान की भरपाई संवेदक से की जायेगी।</p> <p>7.रसोइयो को अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा व दायित्व की पुर्ति करना।</p> <p>8.अधीक्षक के आदेशानुसार समय-समय पर रसोई संबंधि कार्य निर्देशों की पालना करना।</p> <p>9.प्रातः एवं रात्रि भोजन/नाश्ता उपरांत ड्युटी समाप्ती से पूर्व रसोई के सम्पूर्ण कार्य की जिसमें साफ-सफाई चौका बर्तन आदि पूर्ण करने पर ही प्रस्थान करना होगा।</p> <p>10 भोजन संबंधित समाप्त कच्ची सामग्री व ईंधन गृह द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।</p>	<p>गृह में आवासनियों हेतु सुबह का नाश्ता,दोपहर का खाना, रात्रि का भोजन बनाने का कार्य हेतु आवश्यकता है।</p> <p>कार्य दो पारियों में प्रातः 6.00 बजे से 10.00 बजे तक व सायं 4.00बजे से रात्री 8.00 बजे तक। कुल दैनिक 08 घण्टे की ड्यूटी आवश्यक होगी।</p>	साक्षर
4	रवीपर	1 महिला (कुशल)	<p>1.गृह में प्रतिदिन साफ-सफाई पोंछा/झाडु/धुलाई का कार्य करना।</p> <p>2.गृह में शौचालय व स्नानागार में प्रतिदिन</p>	<p>गृह परिसर के सम्पूर्ण सफाई के कार्य हेतु</p>	साक्षर

		<p>दो बार टॉयलेट क्लीनर से सफाई करना व फ्रेशनर टिकिया रखना।</p> <p>3. माह में एक बार गृह के छत की सफाई व जाले आदि को साफ करने का कार्य करना।</p> <p>4. माह में एक बार पानी की टंकियों की सफाई कर दिनांक अंकित करना।</p> <p>5. गृह के बालकोनियो/ दरवाजे/ छज्जे पंखे/ ट्यूबलाईट आदि की माह में एक बार सफाई करना।</p> <p>6. गृह के कमरो में दैनिक रूप से पोंछा-झाडु लगाना व साफ-सफाई हेतु समस्त सामग्री कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p>7. अन्य कार्य जो अधीक्षक निर्देशित करें।</p> <p>8. परिसर में लगे पौधो को पानी पिलाने का कार्य।</p> <p>9. परिसर के मुख्य द्वार के बाहर की साफ सफाई करना।</p> <p>10. पीने का पानी टंकियो में भरना।</p>	<p>प्रातः 8.00 से सायं 4.00 बजे तक अथवा 4 घण्टे प्रातः व 4 घण्टे सांय जैसी भी स्थिति हो प्रतिदिन 8 घण्टे की ड्यूटी आवश्यक है।</p>	
5	सहायक कर्मचारी	<p>1 अकुशल (महिला/पुरुष)</p> <p>1. गृह के अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ के कार्यों में सहयोग उपलब्ध करवाना।</p> <p>2. आवासनियों से मिलने आने वाले आगंतुकों को आवासनियोंसे मुलाकात करवाना।</p> <p>3. गृह में आने वाले अतिथियों एवं भामाशाहों का सत्कार करना</p> <p>4. गृह में संधारित पत्रावलियों का सुव्यवस्थित रखरखाव में सहयोग करना।</p> <p>5. डाक सम्बन्धी कार्य एवं पानी, बिजली के बिल जमा करवाना।</p> <p>6. गृह में होने वाली बोर्ड/समिति आदि की बैठकों की व्यवस्था में सहयोग करना। उक्त के अतिरिक्त गृह के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य सम्पादित करना एवं निर्देशों का पालन करना।</p>	<p>कार्यालय की आवश्यकतानुसार प्रतिदिन 8 घण्टे की ड्यूटी आवश्यक है।</p>	साक्षर

नोट:-

1. प्रत्येक कामगार अपने स्वयं के खर्चे पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होगा व प्रस्थान करेगा।
2. किसी भी कामगार को गृह में भोजन आदि की सुविधा देय नहीं होगी।
3. सभी कार्य जॉब बैसिस पर ही सम्पादित होंगे।
4. चूंकि संस्था बालिकाओं से संबंधित होने के कारण अति संवेदनशील संस्था है। अतः नियोजित कामगार उच्च नैतिक/ साफ-सुथरी छवि, कर्मठ एवं ईमानदार की ही वांछनीयता रहेगी।
5. नियोजित किये जाने वाले कामगार संस्था की गोपनीयता के लिये सत्यनिष्ठ एवं उत्तरदायी होंगे।
6. नियोजित किये जाने वाले कामगारों का पुलिस सत्यापन कराने के उपरांत ही नियोजित किया जायेगा।
7. समस्त जॉब बैसिस कार्य हेतु समस्त सामग्री यथा भोजन हेतु कच्ची सामग्री शाक सब्जी मसाले ईंधन व साफ-सफाई हेतु फिनाईल/झाडु/पोछा/टायलेट क्लीनर सर्फ एवं स्टेनरी आदि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।